{ KOLKATA } RAPE, MURDER OF DOC

Mamata writes to PM again for stricter laws

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

KOLKATA: West Bengal chief minister Mamata Banerjee on Friday wrote a second letter to Prime Minister Narendra Modi, reiterating her request for stringent central legislation with exemplary punishment for perpetrators of heinous crimes like rape and murder.

Meanwhile, the NHRC has sought an action-taken report from the Kolkata police commissioner on the use of "excessive and brutal" force by the city police on protesters earlier this week during a march to secretariat, Nabanna, against the brutal rape and murder of a postgraduate trainee doctor in the state-run RG Kar hospital on August 9.

"I would reiterate and earnestly request to kindly consider a stringent central legislation and exemplary punishment on heinous crimes of rape and murder with mandatory provision for disposal of cases in a specific time-frame by the trial authorities," Banerjee wrote in the letter to the PM, a copy of which she shared on X.

The chief minister said she was yet to receive a reply from the PM on the issue flagged by her in her previous letter on August 22. Banerjee wrote she has, however, received a communication from the Union women and child development minister Annapurna Devi. Banerjee is yet to respond to mounting condemnation of her administration's lapses in handling the sensational case.

Mamata Banerjee

The BJP was quick to hit back at Banerjee calling her a "liar" and asking her to explain why she has not done anything to ensure implementation of existing "stringent" rules and regulations to protect women in her state.

"It is incumbent on Mamata Banerjee to explain why the Bengal government hasn't done anything for implementing the stringent rules and regulations, which exist for protecting women and girls," BJP IT department's head and co-incharge for West Bengal Amit Malviya posted on X. "Stop writing letters. Answer the questions. You are accountable."

The junior doctors of RG Kar hospital have called for a rally to the Kolkata Police headquarters in Lalabazar on September 2.

रिहा बंधुआ मजदूरों को आर्थिक मदद का प्रस्ताव लाएगा एनएचआरसी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बताया कि वो बचाए गए बंधुआ मजदूरों को तुरंत वित्तीय सहायता देने के मुद्दे को हल करने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आएगा।

जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ बंधुआ मजदूरों के रूप में तस्करी किए गए लोगों के मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले में बहस के दौरान उन्हें तत्काल वित्तीय सहायता देने का मुद्दा उठा। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने कहा कि ऐसे 10 प्रतिशत मजदूरों को भी वित्तीय सहायता या मुआवजा नहीं दिया गया। याची संगठन ने लगभग 11 हजार बच्चों को बचाया है, लेकिन उनमें से 719 को ही वित्तीय सहायता दी गई है। एनएचआरसी के वकील ने कहा कि हितधारकों के साथ बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। पीठ ने एनएचआरसी के वकील से कहा कि वे याचिकाकर्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत कर तौर-तरीकों को अंतिम रूप दें।

मृत डाक्टर की मां बोलीं- ममता की संतान नहीं, इसलिए नहीं समझतीं बेटी खोने का दर्द

सीएम के बयान पर जताया दुख, लोगों से आंदोलन जारी रखने का किया आह्वान

डाक्टर से दरिंदगी

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में दरिंदगी की शिकार हुई महिला डाक्टर की मां ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कोई संतान नहीं हैं इसलिए वह बेटी खोने का दर्द नहीं समझ सकतीं। उन्होंने आगे कहा-'हमें मुख्यमंत्री के उस बयान से काफी दुख हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम न्याय नहीं चाहते। पूरा देश हमारी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहा है और हम न्याय नहीं चाहेंगे? वे चाहे जो बोलें, हम अपना दुख किसी को नहीं समझा सकते।'

उन्होंने न्याय के लिए आंदोलन कर रहे लोगों से इसे जारी रखने का आह्वान करते हुए कहा-'हम पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थे इसलिए हाई कोर्ट गए। अदालत ने यह मामला सीबीआइ को सौंपा है। हमें शुरू से ही अस्पताल प्रशासन पर संदेह था। वह मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था। वहां से हमें वारदात की सूचना बहुत देर से दी गई थी।' वहीं मृतका के पिता ने परिवार व अस्पताल के सहायक अधीक्षक के बीच टेलीफोन पर बातचीत के इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो रहे तीन आडियो क्लिप की पुष्टि करने से इन्कार कर दिया।

उपायुक्त (सेंट्रल डिवीजन) इंदिरा मुखर्जी ने कहा-'हमने उन आडियो क्लिप को सुना है। कोलकाता पुलिस की ओर से इसे कभी आत्महत्या का मामला नहीं बताया गया है।' इसी बीच, अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआइ ने शुक्रवार को लगातार 15वें दिन भी पूछताछ की। उधर, एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल छात्र समाज की ओर से हुए राज्य सचिवालय मार्च के दौरान झड़प की घटनाओं पर कोलकाता पुलिस से रिपोर्ट मांगी है।

जनमत मुद्दा

क्या महिला सुरक्षा के मसले पर समाज के स्तर पर व्यापक पहल की जरूरत है?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं।

पर्ची पर एक डाक्टर लगा रहे हैं न्याय चाहिए की मोहर

जासं, रायगंज : कोलकाता के अस्पताल में महिला डाक्टर के साथ हुई घटना के न्याय की मांग पर बंगाल के रायगंज में डाक्टर देबब्रत राय दवा की पर्ची पर दवा व सलाह लिखने के बाद "न्याय चाहिए" की मोहर लगा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर पर्ची की तस्वीर प्रसारित हो रही है।

महिला मोर्चा ने बंगाल महिला आयोग के कार्यालय पर जड़ा ताला

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : कोलकाता में महिला डाक्टर से दुष्कर्म व हत्या के विरोध में बंगाल भाजपा महिला मोर्चा की नेताओं ने शुक्रवार को राज्य महिला आयोग के कार्यालय पर प्रतीकात्मक ताला जड़ दिया। महिला मोर्चा का आरोप है कि राज्य महिला आयोग बंगाल में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। महिला मोर्चा की शीर्ष नेताओं की अगुआई में हजारों कार्यकर्ता दोपहर में मार्च करते हुए आयोग के कार्यालय के पास पहुंचीं, जहां पुलिस के साथ धक्का-मुक्की हुई। इसके बाद महिला मोर्चा की नेता बारिश में ही धरने पर बैठ गईं और मुख्यमंत्री ममता के इस्तीफे और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। पुलिस ने पांच लोगों के प्रतिनिधिमंडल को आयोग कार्यालय के अंदर जाने की इजाजत दी। इसके बाद पूर्व सांसद लाकेट चटर्जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री देबश्री चौधरी व विधायक अग्निमित्रा पाल सहित पांच महिला नेता अंदर गईं और अधिकारियों से मुलाकात के बाद आयोग कार्यालय के मुख्य गेट पर प्रतीकात्मक ताला लटका दिया। अग्निमित्रा पाल ने पत्रकारों से कहा कि राज्य महिला आयोग कोई काम नहीं करता है। उधर, पीड़िता को न्याय और दोषियों को जल्द फांसी की सजा की मांग पर तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद (टीएमसीपी) के सदस्यों ने कालेजों के सामने धरना प्रदर्शन किया। इसी बीच बंगाल के राज्यपाल डा. सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री शाह से उनके आवास पर मुलाकात कर ताजा हालात पर रिपोर्ट सौंपी।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

HINDUSTAN, Delhi, 31.8.2024
Page No. 14, Size:(2.88)cms X (6.51)cms.

एनएचआरसी मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए प्रस्ताव लाएगा

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शुक्रवार को कहा कि वह बाल एवं बंधुआ मजदूरी से मुक्त सभी बच्चों/लोगों को वित्तीय मदद मुहैया कराने को ठोस प्रस्ताव लाएगा।

बंधुआ मजदूरी खत्म करने और उनके मौलिक अधिकारों के लिए समुचित नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आयोग ने यह जानकारी दी। जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ के समक्ष आयोग ने कहा कि वह मुद्दे को हल करने को प्रस्ताव लेकर आएगा।

रिहा कराए गए बंधुआ मजदूरों को वित्तीय सहयोग के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा: एनएचआरसी

वैभव न्यूज ■ नई दिल्ली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह बचाए गए बंधुआ मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के मुद्दे को हल करने के लिए सभी हितधारकों के साथ चर्चा करेगा और एक ठोस प्रस्ताव लेकर आएगा।

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ बंधुआ मजदूरों के रूप में

तस्करी किए गए लोगों के मौलिक अधिकारों को लागू करने संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान उन मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का मुद्दा उठा। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एच. एस. फुल्का ने कहा कि ऐसे 10 प्रतिशत मजदूरों को भी वित्तीय सहायता या मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता संगठन ने करीब 11,000 बच्चों को बचाया है, लेकिन उनमें से केवल 719 को ही वित्तीय सहायता दी गई। एनएचआरसी की वकील ने कहा कि वह हितधारकों के साथ बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा कर सकती हैं। पीठ ने एनएचआरसी की वकील से कहा कि वे याचिकाकर्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत कर तौर-तरीकों को अंतिम रूप दें। पीठ ने कहा, एनएचआरसी की वकील ने कहा कि वह सभी हितधारकों के साथ चर्चा करेंगी और एक ठोस प्रस्ताव लेकर आएंगी, ताकि बचाए गए बंधुआ मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता पहुंचाने के मुद्दे को हल किया जा सके। पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तारीख निर्धारित की। शीर्ष अदालत ने जुलाई 2022 में याचिका पर सुनवाई को लेकर सहमति जताई थी।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

HINDU, Kochi, 31.8.2024
Page No. 9, Size:(9.67)cms X (6.76)cms.

Protests continue to rock Kolkata; Mamata writes to PM Modi again

Shiv Sahay Singh
KOLKATA

More than 20 days after the rape and murder of a doctor at the R.G. Kar Medical College and Hospital, protests continued to rock the city on Friday with leaders of the Bharatiya Janata Party's women's wing putting a giant-sized model of a lock on the gate of the West Bengal State Women's Commission.

BJP leader Agnimitra Paul and Mahila Morcha activists marching towards West Bengal Commission for Women on Friday. PTI

Reiterating her request for stringent Central laws against crimes of sexual assault, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Friday again wrote to Prime Minister Narendra Modi saying that she received no reply from him for her previous letter. Referring to a letter by Union Minister of Women and Child Development Annapurna Devi, the Chief Minister said that it "barely attends the gravity of the issue" raised by her.

In another development, the Chief Medical Officer of Health, Purba Medinipur, sent notices to 29 clinics and hospitals in the district for violating the Clinical Establishment Act.

This comes a day after Ms. Banerjee clarified that she did not threaten protesting resident doctors at a public meeting on August 28.

The National Human Rights Commission issued a notice to Kolkata Police Commissioner Vineet Goyal seeking a report on the "barbaric" and "brutal" assault on the protesters during the 'March to Nabanna' on August 27.

HINDUSTAN TIMES, Mumbai, 31.8.2024
Page No. 10, Size:(6.03)cms X (11.09)cms.

{ KOLKATA } RAPE, MURDER OF DOC

Mamata writes to PM again for stricter laws

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

KOLKATA: West Bengal chief minister Mamata Banerjee on Friday wrote a second letter to Prime Minister Narendra Modi, reiterating her request for stringent central legislation with exemplary punishment for perpetrators of heinous crimes like rape and murder.

Meanwhile, the NHRC has sought an action-taken report from the Kolkata police commissioner on the use of "excessive and brutal" force by the city police on protesters earlier this week during a march to secretariat, Nabanna, against the brutal rape and murder of a postgraduate trainee doctor in the state-run RG Kar hospital on August 9.

"I would reiterate and earnestly request to kindly consider a stringent central legislation and exemplary punishment on heinous crimes of rape and murder with mandatory provision for disposal of cases in a specific time-frame by the trial authorities," Banerjee wrote in the letter to the PM, a copy of which she shared on X.

The chief minister said she was yet to receive a reply from the PM on the issue flagged by her in her previous letter on August 22. Banerjee wrote she has, however, received a communication from the Union women and child development minister Annapurna Devi. Banerjee is yet to respond to mounting condemnation of her administration's lapses in handling the sensational case.

Mamata Banerjee

The BJP was quick to hit back at Banerjee calling her a "liar" and asking her to explain why she has not done anything to ensure implementation of existing "stringent" rules and regulations to protect women in her state.

"It is incumbent on Mamata Banerjee to explain why the Bengal government hasn't done anything for implementing the stringent rules and regulations, which exist for protecting women and girls," BJP IT department's head and co-incharge for West Bengal Amit Malviya posted on X. "Stop writing letters. Answer the questions. You are accountable."

The junior doctors of RG Kar hospital have called for a rally to the Kolkata Police headquarters in Lalabazar on September 2.

PRABHAT KHABAR, Kolkata, 31.8.2024
Page No. 3, Size:(28.15)cms X (12.36)cms.

सख्ती. छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना पर मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोलकाता पुलिस को भेजा नोटिस

संवाददाता, कोलकाता

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शुक्रवार को कोलकाता पुलिस को नोटिस जारी कर 27 अगस्त को 'नबान्न अभियान' के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा किये गये बल प्रयोग पर स्पष्टीकरण मांगा है. यह अभियान आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की महिला जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में शुरू किया गया था.

सूत्रों के अनुसार, एनएचआरसी ने अगले 14 दिनों के भीतर कोलकाता पुलिस से रिपोर्ट मांगी है. आयोग का मानना है कि सोशल मीडिया पर छात्रों के एक समूह द्वारा आहूत नबान्न अभियान में भाग लेनेवाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई मानवाधिकारों का उल्लंघन है.

क्या है मामला: गौरतलब है कि 27 अगस्त की दोपहर को हावड़ा समेत राज्य के कुछ हिस्से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद रणक्षेत्र में तब्दील हो गये थे. राज्य सचिवालय ने पुलिस से प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करने को कहा था. इस दौरान कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गये. इस सिलसिले में कुल 220 गिरफ्तारियां की गयीं. इसके अलावा, ऑपरेशन से पहले एहतियात के तौर पर 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया था कि अगर एहतियाती तौर पर गिरफ्तारियां नहीं की जातीं, तो स्थिति और खराब हो सकती थी.

नबान्न अभियान के दौरान पुलिस पर हमला करने के आरोप में और तीन अरेस्ट

कोलकाता. पश्चिम बंग छात्र समाज के आह्वान पर नबान्न अभियान के दौरान पुलिस पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने और तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इसमें बड़ाबाजार थाने की पुलिस ने दो हमलावरों को गिरफ्तार किया है. इनके नाम सुब्रत मजूमदार और देवायन दास बताये गये हैं. दोनों को अदालत में पेश करने पर उन्हें पांच सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. वहीं, साउथ पोर्ट थाने की पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. अदालत ने उसे चार सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. इसे लेकर अब तक कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

नबान्न अभियान में शामिल होने के लिए दिये गये थे रुपये!

- कोलकाता पुलिस के हाथों गिरफ्तार आरोपियों ने किया खुलासा

कोलकाता. पश्चिम बंग छात्र समाज के आह्वान पर नबान्न अभियान में शामिल होने के लिए कुछ युवकों को रुपये दिये गये थे. कोलकाता पुलिस के हाथों गिरफ्तार हमलावरों से पूछताछ में कुछ लोगों ने यह जानकारी दी है. पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने नबान्न अभियान के दौरान पुलिस पर हमला किया था, ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गयी, तो इनमें से कुछ युवकों का कहना है कि वे सोशल मीडिया में फैल रही जानकारी से प्रेरित होकर इस अभियान में शामिल होने आये थे. हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें इस अभियान में शामिल होने के लिए रुपये दिये गये थे. लालबाजार सूत्र बताते हैं कि उसे कुछ लोगों के नाम मिले हैं, जिनपर इन लोगों को रुपये देकर इस अभियान में आने को कहा गया था. इन लोगों से इस बारे में पूछताछ की जायेगी. अगर वे कोई सटीक जानकारी नहीं दे सके, तो ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जायेगी.

नबान्न अभियान के पीछे किसका हाथ, पता लगा रही पुलिस

कोलकाता. गत मंगलवार को पश्चिम बंग छात्र समाज के नबान्न अभियान के पीछे किसका हाथ है, पुलिस इसका पता लगा रही है. पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच में पाया गया कि अभियान के दिन कॉलेज स्ट्रीट के पास एक गाड़ी से बड़ी संख्या में टीशर्ट लाकर प्रदर्शनकारियों में बांटी गयी थी. उक्त टीशर्ट में से कुछ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ ही भड़काऊ संदेश लिखे हुए थे, जिससे समाज में अशांति फैलने की आशंका थी. इस कारण पुलिस इस अभियान के पीछे किसका हाथ है, यह पता लगाने की कोशिश कर रही है.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

NORTH EAST TIMES, Guwahati, 31.8.2024
Page No. 5, Size:(28.92)cms X (25.15)cms.

Rights body's notice to Kolkata cops over 'barbaric' action on Nabanna protesters

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday issued a notice to Kolkata Police seeking a report on the "barbaric" and "brutal" assault on the protesters during the 'Nabanna Abhijan' rallies.

In its notice, issued to the Kolkata Police Commissioner, the human rights body has sought an "action taken" report in 14 days. On August 27, the 'Nabanna Abhijan' march was called demanding justice for the 31-year-old trainee doctor, capital punishment for the culprit, and the resignation of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee.

Large-scale violence was reported in Kolkata and adjacent Howrah during the 'Nabanna Abhijan' protest march after protestors, aiming to reach the West Bengal state secretariat, Nabanna, fought pitched battles with the police at multiple stoppage points. The violence, which lasted for nearly four hours, led to several injuries on both sides, with senior police officers and women protestors among those who were hurt.

After the protest, more than 200 people were arrested from across the state by the police.

Police resorted to large-scale lathi-charge, unleashed water cannons and lobbed tear gas shells to disperse the aggressive crowd who poured in from multiple converging points at Nabanna. The 'Nabanna Abhijan' call was given by an unregistered student body 'Paschim Banga Chhatra Samaj' and a dissident state government employees' platform 'Sangrami Joutha Mancha' who demanded the resignation of state Chief Minister Mamata Banerjee over the alleged rape-murder of a medic at RG Kar Medical College and Hospital on August 9. PTI

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गृह विभाग को सौंपा रिपोर्ट भिजवाने का जिम्मा

26 जिलों ने दबाए मानवाधिकार के बड़े मामले, 48 घंटे में जवाब तलब

हि एक्सक्लूसिव

कुंदन कुमार

मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में चल रहे 63 मामलों की फाइल जिलों में अधिकारियों ने दबा रखी है। आयोग ने गृह विभाग को सभी जिलों की रिपोर्ट भिजवाने की जिम्मेवारी सौंपी है। इसके बाद गृह विभाग ने जिलों को रिपोर्ट के लिए 31 अगस्त का समय निर्धारित कर दिया है।

गृह विभाग की विशेष शाखा के विशेष सचिव के सुहिता अनुपम ने सभी डीएम को कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज ये मामले बेहद गंभीर किस्म के हैं, जिनमें मुख्य सचिव से लेकिर जिला पदधिकारी और उनके अधीनस्थ अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में लंबित इन मामलों में सरकार को या संबंधित जिला प्रशासन को अपना पक्ष रखना है, जो समय पर नहीं रखा जा रहा है। विशेष सचिव ने सभी डीएम को इसे 31 अगस्त तक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने और इसकी सूचना गृह विभाग को देने का निर्देश दिया है।

मुजफ्फरपुर डीएम-एसएसपी को इन मामलों में देना है जवाब

आई हॉस्पिटल कांड में भी रिपोर्ट अधूरी, आयोग गंभीर

1 मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल कांड में भी पीड़ितों की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामला दर्ज कराया गया। इसमें आयोग ने प्रशासन को दो-दो लाख रुपये की अंतरित सहायता देने का आदेश दिया। यह राशि उस पैसे के अलावा है, जो उन्हें एक-एक लाख पूर्व में दिये गए थे। जिला प्रशासन की ओर से पीड़ितों को दो-दो लाख का भुगतान कर रिपोर्ट आयोग को सौंपनी है, लेकिन यह रिपोर्ट अभी तक लंबित है, जिसपर आयोग ने गंभीरता दिखायी है।

अधिवक्ता की आंख फोड़ने के मामले में भी रिपोर्ट लंबित

2 कुछ माह पहले अधिवक्ता पंकज कुमार पर डंडा चलाने के दौरान उनकी आंखें फूट गईं और रोशनी चली गई। अधिवक्ता ने इस मामले में दोषी पुलिस जवान पर कार्रवाई के लिए आयोग से गुहार लगायी। इस मामले में भी एसएसपी के स्तर से अंतिम कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को अब तक नहीं मिली है। आयोग ने गृह विभाग के माध्यम से इस मामले में अंतिम कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है, ताकि मामले में फैसला सुनाया जा सके।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठाये आरोप भी अनसुलझे

3 तीसरा मामला झपहां निवासी मो. शाहबाज का है, जिसकी मौत तालाब में डूबने से बतायी गई है। इस मामले में मृतक के पिता ने एसकेएमसीएच के चिकित्सक पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत देने का आरोप लगाया है। पिता ने कहा है कि उसके पुत्र की हत्या कर तालाब में शव फेंक दिया गया था। उसके बदन पर चोट के निशान थे, लेकिन चिकित्सक ने डूबने से मौत बतायी है। इस मामले में आयोग ने एसकेएमसीएच से सीएमओ व एसकेएमसीएच प्राचार्य से कार्रवाई प्रतिवेदन की मांग कर रखी है, जो आयोग को अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

जेल में मृत गणेश शर्मा की रिपोर्ट लंबित

4 केंद्रीय कारा में बंदी गणेश शर्मा की मौत के बाद उसके परिजनों ने उसकी अस्वाभाविक मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की। आयोग ने इस मामले में जेल अधीक्षक से विस्तृत प्रतिवेदन मांगा। इसके जवाब में 26 अप्रैल से जेल अधीक्षक ने बंदी गणेश शर्मा की स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट, इलाज से संबंधित प्रतिवेदन, मौत के बाद इंक्वेस्ट रिपोर्ट व पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयोग को सौंप दी। आयोग इसके बाद बंदी की एमईआर रिपोर्ट मांगी है, जो जेल अधीक्षक अभी तक नहीं दे पाये हैं।

डीबीआर मामले में भी कार्रवाई रिपोर्ट तलब

5 मुजफ्फरपुर के एक और गंभीर मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जिले से रिपोर्ट का इंतजार है। यह मामला निजी कंपनी डीबीआर से जुड़ा है, जिसमें काम करने वाली पीड़िता ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसमें आयोग ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आयोग के अनुसार उसे अब तक कार्रवाई रिपोर्ट नहीं मिली है। गृह विभाग ने इस मामले में भी कार्रवाई रिपोर्ट 31 अगस्त तक अपलोड करने का निर्देश दिया है।

HINDUSTAN, GAYA, 31.8.2024
Page No. 8, Size:(12.01)cms X (12.65)cms.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गृह विभाग को सौंपा रिपोर्ट भिजवाने का जिम्मा

26 जिलों ने दबाए मानवाधिकार के बड़े मामले, 48 घंटे में जवाब तलब

हि एक्सक्लूसिव

■ कुंदन कुमार

मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में चल रहे 63 मामलों की फाइल जिलों में अधिकारियों ने दबा रखी है। आयोग ने गृह विभाग को सभी जिलों की रिपोर्ट भिजवाने की जिम्मेवारी सौंपी है। इसके बाद गृह विभाग ने जिलों को रिपोर्ट के लिए 31 अगस्त का समय निर्धारित कर दिया है।

गृह विभाग की विशेष शाखा के विशेष सचिव के सुहिता अनुपम ने सभी डीएम को कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज ये मामले बेहद गंभीर किस्म के हैं, जिनमें मुख्य सचिव से लेकिर जिला पदधिकारी और उनके अधीनस्थ अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में लंबित इन मामलों में सरकार को या संबंधित जिला प्रशासन को अपना पक्ष रखना है, जो समय पर नहीं रखा जा रहा है।

विशेष सचिव ने सभी डीएम को इसे 31 अगस्त तक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने और इसकी सूचना गृह विभाग को देने का निर्देश दिया है।

मुजफ्फरपुर डीएम-एसएसपी को इन मामलों में देना है जवाब

आई हॉस्पिटल कांड में भी रिपोर्ट अधूरी

1 मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल कांड में भी पीड़ितों की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामला दर्ज कराया गया। इसमें आयोग ने प्रशासन को दो-दो लाख रुपये की अंतरित सहायता देने का आदेश दिया। यह राशि उस पैसे के अलावा है, जो उन्हें एक-एक लाख पूर्व में दिये गए थे। जिला प्रशासन की ओर से पीड़ितों को दो-दो लाख का भुगतान कर रिपोर्ट आयोग को सौंपनी है, लेकिन यह रिपोर्ट अभी तक लंबित है, जिसपर आयोग ने गंभीरता दिखायी है।

अधिवक्ता की आंख फोड़ने मामले में भी रिपोर्ट लंबित

2 कुछ माह पहले अधिवक्ता पंकज कुमार पर डंडा चलाने के दौरान उनकी आंखें फूट गईं और रोशनी चली गई। अधिवक्ता ने इस मामले में दोषी पुलिस जवान पर कार्रवाई के लिए आयोग से गुहार लगायी। इस मामले में भी एसएसपी के स्तर से अंतिम कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को अब तक नहीं मिली है। आयोग ने गृह विभाग के माध्यम से इस मामले में अंतिम कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है, ताकि मामले में फैसला सुनाया जा सके।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठाये आरोप अनसुलझे रह गए

3 तीसरा मामला झपहां निवासी मो. शाहबाज का है, जिसकी मौत तालाब में डूबने से बतायी गई है। इस मामले में मृतक के पिता ने एसकेएमसीएच के चिकित्सक पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत देने का आरोप लगाया है। पिता ने कहा है कि उसके पुत्र की हत्या कर तालाब में शव फेंक दिया गया था। उसके बदन पर चोट के निशान थे, लेकिन चिकित्सक ने डूबने से मौत बतायी है। इस मामले में आयोग ने एसकेएमसीएच से सीएमओ व एसकेएमसीएच प्राचार्य से कार्रवाई प्रतिवेदन की मांग कर रखी है, जो आयोग को अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

जेल में मृत गणेश शर्मा की रिपोर्ट लंबित

4 केंद्रीय कारा में बंदी गणेश शर्मा की मौत के बाद उसके परिजनों ने उसकी अस्वाभाविक मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की। आयोग ने इस मामले में जेल अधीक्षक से विस्तृत प्रतिवेदन मांगा। इसके जवाब में 26 अप्रैल से जेल अधीक्षक ने बंदी गणेश शर्मा की स्वास्थ जांच रिपोर्ट, इलाज से संबंधित प्रतिवेदन, मौत के बाद इंक्वेस्ट रिपोर्ट व पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयोग को सौंप दी। आयोग इसके बाद बंदी की एमईआर रिपोर्ट मांगी है, जो जेल अधीक्षक अभी तक नहीं दे पाये हैं।

डीबीआर मामले में भी कार्रवाई रिपोर्ट तलब

5 मुजफ्फरपुर के एक और गंभीर मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जिले से रिपोर्ट का इंतजार है। यह मामला निजी कंपनी डीबीआर से जुड़ा है, जिसमें काम करने वाली पीड़िता ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसमें आयोग ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आयोग के अनुसार उसे अब तक कार्रवाई रिपोर्ट नहीं मिली है। गृह विभाग ने इस मामले में भी कार्रवाई रिपोर्ट 31 अगस्त तक अपलोड करने का निर्देश दिया है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

TIMES OF INDIA, Kolkata, 31.8.2024
Page No. 4, Size:(3.81)cms X (13.72)cms.

Why lathi charge vandals, NHRC asks KP

Tamaghna.Banerjee
@timesofindia.com

Kolkata: The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday issued a notice to Kolkata Police, seeking an explanation on alleged police action on protesters during Tuesday's Nabanna Abhijan, in which 56 cops were injured, five of them still in hospital with severe injuries, on being attacked with bricks, bottles and guard rails.

The panel has sought a report within two weeks and a senior police officer said they would respond within time after consulting legal experts.

The march was called by a group, Paschimbanga Chhatra Samaj, to condemn the RG Kar rape and murder.

So far, 252 people have been arrested on charges of vandalism, attempt to murder and unlawful assembly. BJP's Suvendu Adhikari had claimed 133 protesters, including 17 women, were injured.

The mob, comprising a large number of people well beyond a 'student's age', had dismantled barricades, trying to reach Nabanna and also attacked cops with bricks and bottles. Police used water cannons, lobbed tear gas shells and resorted to lathi charge at six locations.

PRABHAT KHABAR, GAYA, 31.8.2024
Page No. 16, Size:(15.35)cms X (29.21)cms.

रिहा कराये गये बंधुआ मजदूरों को वित्तीय सहयोग के लिए प्रस्ताव लाया जायेगा : एनएचआरसी

- 28 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित ईंट भट्ठे से गया के कुछ बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया था

एजेंसियां, नयी दिल्ली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के मुद्दे को हल करने के लिए सभी हितधारकों के साथ चर्चा करेगा और एक ठोस प्रस्ताव लेकर आयेगा. न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ बंधुआ मजदूरों के रूप में तस्करी किये गये लोगों के मौलिक अधिकारों को लागू करने संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस दौरान मुक्त मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का मुद्दा उठा. याचिकाकर्ताओं में से एक ने कहा है कि उसे और कुछ अन्य बंधुआ मजदूरों को 28 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक ईंट भट्ठे से बचाया गया था. उन्हें बिहार के गया जिला स्थित उनके पैतृक गांव से एक गैर-पंजीकृत ठेकेदार द्वारा तस्करी कर लाया गया था. याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें और उनके साथी श्रमिकों को न्यूनतम वैधानिक मजदूरी के भुगतान के बिना काम करने के लिए मजबूर किया गया और उनके आवागमन एवं रोजगार के मौलिक अधिकारों पर गंभीर रूप से अंकुश लगाया गया.

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने शीर्ष अदालत को बताया कि ऐसे 10 प्रतिशत मजदूरों को भी वित्तीय सहायता या मुआवजा नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता संगठन ने करीब 11,000 बच्चों को बचाया है, लेकिन उनमें से केवल 719 को ही वित्तीय सहायता दी गयी. एनएचआरसी की वकील ने कहा कि वह हितधारकों के साथ बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा कर सकती हैं. पीठ ने एनएचआरसी की वकील से कहा कि वह याचिकाकर्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत कर तौर-तरीकों को अंतिम रूप दें. पीठ ने कहा, ''एनएचआरसी की वकील ने कहा कि वह सभी हितधारकों के साथ चर्चा करेंगी और एक ठोस प्रस्ताव लेकर आयेंगी, ताकि मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता पहुंचाने के मुद्दे को हल किया जा सके. पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तारीख निर्धारित की. शीर्ष अदालत ने जुलाई 2022 में याचिका पर सुनवाई को लेकर सहमति जतायी थी और याचिका पर केंद्र, एनएचआरसी और कुछ राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा था.

Telangana Today

Demolitions: BRS seeks NHRC action

STATE BUREAU
Hyderabad

Reacting to the shocking demolition of houses of the poor and the physically challenged in Mahabubnagar that sparked outrage and widespread condemnation, BRS leader and former Minister V Srinivas Goud on Friday called for the intervention of the National Human Rights Commission to ensure justice to the victims.

Addressing a news conference at Telangana Bhavan, he termed the treatment meted out to victims as most brutal and inhuman. The demolition, which took place at 3 am, left many visually impaired residents unable to save even their essential commodities. Goud questioned the necessity of conducting the demolition at such an early hour, highlighting the plight of the displaced who were left without basic necessities.

These individuals, many of whom were blind or physically challenged, built their homes with the pension money provided under the BRS regime. What the administration demolished were not just houses, but the dreams of a happy life, he said, emphasizing that the tiny houses, though not of significant monetary value, represented the hard-earned efforts of the residents. Goud urged the courts to take up the issue suo moto and wanted even the general public to rise above political considerations to support the victims. He demanded that the government rebuild the demolished houses at the same location and ensure the rehabilitation of the displaced with a sense of urgency. The government must show a human face and refrain from displacing the physically challenged, who genuinely deserved support and aid that various organizations have been extending, he added.

A woman searches for her belongings amid the rubble following demolition of houses in Mahabubnagar on Friday.

Deeply anguished, says Praveen Kumar

HYDERABAD: Expressing deep anguish over the demolition of houses belonging to physically challenged and visually challenged individuals in Mahbubnagar, BRS leader RS Praveen Kumar recounted a heart-wrenching scene where a young girl, still in her school uniform, was seen searching for her school books amidst the rubble of her demolished home.

"I could not hold my tears at the pathetic situation of the family," he said, questioning how Chief Minister A. Revanth Reddy could sleep peacefully while such actions were taking place. Praveen Kumar highlighted that 400 policemen were deployed to demolish the homes of vulnerable individuals, questioning why the same force was not used against influential figures like Tirupati Reddy, the Chief Minister's brother. He accused the Congress government of having double standards, acting swiftly against the poor while showing leniency towards the wealthy and influential. He specifically mentioned the encroachments related to Tirupati Reddy's house in Durgam Cheruvu, questioning the lack of action in that case. While acknowledging the importance of protecting the environment, Praveen Kumar emphasized that there should not be different yardsticks for the rich and the poor.

Provide alternatives to the poor: CPM

HYDERABAD: The CPI (M) State unit demanded the State government not to demolish the houses of the poor near nalas or lake areas without providing any alternative.

The poor and middle-class should not be rendered homeless. Before clearing any structures near nalas and lake areas, the State government should provide alternative provisions, CPI (M) State Secretary Tammineni Veerabhadram said in a statement here on Friday. About 12 years ago, the past government allotted pattas to differently-abled persons at Christianpally in Mahabubnagar. Officials demolished the structures, leaving the residents, living there since many years, homeless, he said.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, Jaipur, 31.8.2024
Page No. 3, Size:(17.11)cms X (10.90)cms.

बेसमेंट में पानी भरने से 3 जनों की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

लीगलरिपोर्टर|जयपुर

राष्ट्रीय मानवाधिकार, आयोग ने जयपुर के वीकेआई एरिया के ध्वज नगर में एक अगस्त को आई भारी बारिश के दौरान बेसमेंट में पानी भरने से हुई तीन जनों की मौत मामले में प्रशासनिक लापरवाही व पीड़ितों को मुआवजे के संबंध में प्रदेश के सीएस, जिला कलेक्टर व जेडीसी को नोटिस जारी कर उनसे कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने इनसे पूछा है कि इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही को क्यों ना इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार माना जाए। आयोग ने यह निर्देश राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक बूंदी निवासी चर्मेश शर्मा की शिकायत पर दिया। चर्मेश शर्मा ने जयपुर में आई बारिश से हुई तीन जनों की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में स्थानीय प्रशासन की बारिश के दौरान आपदा प्रबंधन में हुई लापरवाही से जल भराव होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे तीन जनों की मौत हुई है। इसलिए इसके जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिया जाए। गौरतलब है कि एक अगस्त को भारी बारिश के चलते जयपुर शहर में जल भराव हो गया था और इसके चलते वीकेआई एरिया में तीन जनों की मौत हो गई थी।

MEGHALAYA GUARDIAN, Shillong, 31.8.2024
Page No. 7, Size:(13.10)cms X (45.01)cms.

Rights body's notice to Kolkata cops over 'barbaric' action on Nabanna protesters

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday issued a notice to Kolkata Police seeking a report on the "barbaric" and "brutal" assault on the protesters during the 'Nabanna Abhijan' rallies.

In its notice, issued to the Kolkata Police Commissioner, the human rights body has sought an "action taken" report in 14 days. On August 27, the 'Nabanna Abhijan' march was called demanding justice for the 31-year-old trainee doctor, capital punishment for the culprit, and the resignation of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee.

Large-scale violence was reported in Kolkata and adjacent Howrah during the 'Nabanna Abhijan' protest march after protestors, aiming to reach the West Bengal state secretariat, Nabanna, fought pitched battles with the police at multiple stoppage points. The violence, which lasted for nearly four hours, led to several injuries on both sides, with senior police officers and women protestors among those who were hurt.

After the protest, more than 200 people were arrested from across the state by the police.

Police resorted to large-scale lathi-charge, unleashed water cannons and lobbed tear gas shells to disperse the aggressive crowd who poured in from multiple converging points at Nabanna. The 'Nabanna Abhijan' call was given by an unregistered student body 'Paschim Banga Chhatra Samaj' and a dissident state government employees' platform 'Sangrami Joutha Mancha' who demanded the resignation of state Chief Minister Mamata Banerjee over the alleged rape-murder of a medic at RG Kar Medical College and Hospital on August 9.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

HINDUSTAN, Patna, 31.8.2024
Page No. 10, Size:(21.46)cms X (17.86)cms.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गृह विभाग को सौंपा रिपोर्ट भिजवाने का जिम्मा

26 जिलों ने दबाए मानवाधिकार के बड़े मामले, 48 घंटे में जवाब तलब

हि एक्सक्लूसिव

■ कुंदन कुमार

मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में चल रहे 63 मामलों की फाइल जिलों में अधिकारियों ने दबा रखी है। आयोग ने गृह विभाग को सभी जिलों की रिपोर्ट भिजवाने की जिम्मेवारी सौंपी है। इसके बाद गृह विभाग ने जिलों को रिपोर्ट के लिए 31 अगस्त का समय निर्धारित कर दिया है।

गृह विभाग की विशेष शाखा के विशेष सचिव के सुहिता अनुपम ने सभी डीएम को कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज ये मामले बेहद गंभीर किस्म के हैं, जिनमें मुख्य सचिव से लेकिर जिला पदधिकारी और उनके अधीनस्थ अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में लंबित इन मामलों में सरकार को या संबंधित जिला प्रशासन को अपना पक्ष रखना है, जो समय पर नहीं रखा जा रहा है। विशेष सचिव ने सभी डीएम को इसे 31 अगस्त तक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने और इसकी सूचना गृह विभाग को देने का निर्देश दिया है।

मुजफ्फरपुर डीएम-एसएसपी को इन मामलों में देना है जवाब

आई हॉस्पिटल कांड में भी रिपोर्ट अधूरी

1 मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल कांड में भी पीड़ितों की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामला दर्ज कराया गया। इसमें आयोग ने प्रशासन को दो-दो लाख रुपये की अंतरित सहायता देने का आदेश दिया। यह राशि उस पैसे के अलावा है, जो उन्हें एक-एक लाख पूर्व में दिये गए थे। जिला प्रशासन की ओर से पीड़ितों को दो-दो लाख का भुगतान कर रिपोर्ट आयोग को सौंपनी है, लेकिन यह रिपोर्ट अभी तक लंबित है, जिसपर आयोग ने गंभीरता दिखायी है।

अधिवक्ता की आंख फोड़ने मामले में भी रिपोर्ट लंबित

2 कुछ माह पहले अधिवक्ता पंकज कुमार पर डंडा चलाने के दौरान उनकी आंखें फूट गईं और रोशनी चली गई। अधिवक्ता ने इस मामले में दोषी पुलिस जवान पर कार्रवाई के लिए आयोग से गुहार लगायी। इस मामले में भी एसएसपी के स्तर से अंतिम कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को अब तक नहीं मिली है। आयोग ने गृह विभाग के माध्यम से इस मामले में अंतिम कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है, ताकि मामले में फैसला सुनाया जा सके।

डीबीआर मामले में भी कार्रवाई रिपोर्ट तलब

3 मुजफ्फरपुर के एक और गंभीर मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जिले से रिपोर्ट का इंतजार है। यह मामला निजी कंपनी डीबीआर से जुड़ा है, जिसमें काम करने वाली पीड़िता ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसमें आयोग ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आयोग के अनुसार उसे अब तक कार्रवाई रिपोर्ट नहीं मिली है। गृह विभाग ने इस मामले में भी कार्रवाई रिपोर्ट 31 अगस्त तक अपलोड करने का निर्देश दिया है।

HINDUSTAN TIMES, Chandigarh, 31.8.2024
Page No. 6, Size:(7.22)cms X (13.77)cms.

{ KOLKATA } RAPE, MURDER OF DOC

Mamata writes to PM again for stricter laws

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

KOLKATA: West Bengal chief minister Mamata Banerjee on Friday wrote a second letter to Prime Minister Narendra Modi, reiterating her request for stringent central legislation with exemplary punishment for perpetrators of heinous crimes like rape and murder.

Meanwhile, the NHRC has sought an action-taken report from the Kolkata police commissioner on the use of "excessive and brutal" force by the city police on protesters earlier this week during a march to secretariat, Nabanna, against the brutal rape and murder of a postgraduate trainee doctor in the state-run RG Kar hospital on August 9.

"I would reiterate and earnestly request to kindly consider a stringent central legislation and exemplary punishment on heinous crimes of rape and murder with mandatory provision for disposal of cases in a specific time-frame by the trial authorities," Banerjee wrote in the letter to the PM, a copy of which she shared on X.

The chief minister said she was yet to receive a reply from the PM on the issue flagged by her in her previous letter on August 22. Banerjee wrote she has, however, received a communication from the Union women and child development minister Annapurna Devi. Banerjee is yet to respond to mounting condemnation of her administration's lapses in handling the sensational case.

Mamata Banerjee

The BJP was quick to hit back at Banerjee calling her a "liar" and asking her to explain why she has not done anything to ensure implementation of existing "stringent" rules and regulations to protect women in her state.

"It is incumbent on Mamata Banerjee to explain why the Bengal government hasn't done anything for implementing the stringent rules and regulations, which exist for protecting women and girls," BJP IT department's head and co-incharge for West Bengal Amit Malviya posted on X. "Stop writing letters. Answer the questions. You are accountable."

The junior doctors of RG Kar hospital have called for a rally to the Kolkata Police headquarters in Lalabazar on September 2.

JANTA SE RISHTA, Online, 30.8.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Andhra : शेषाचलम मुठभेड़ मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार और एनएचआरसी को निर्देश दिए

https://jantaserishta.com/local/andhra-pradesh/andhra-collector-thameem-ansari-highlights-benefits-of-sports-3493826?infinitescroll=1

Renuka Sahu29 Aug 2024 9:55 AM

विजयवाड़ा VIJAYAWADA : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को वर्ष 2015 में शेषाचलम मुठभेड़ में 'लाल चंदन तस्करों' के शिकार हुए लोगों के परिवारों द्वारा मामले में पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र के खिलाफ दायर विरोध याचिका की सुनवाई पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही, मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति सी रवि की खंडपीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मामले की जांच पर स्पष्टता देने को कहा, क्योंकि मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में हो रही है।

इसने एनएचआरसी के वकील को निर्देश दिया कि वे इस मुद्दे पर समानांतर जांच जारी रखें या नहीं, इस पर निर्णय लें। बाद में मामले की सुनवाई अगले महीने के लिए स्थगित कर दी गई।मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर याचिका के बाद एनएचआरसी ने मामले की स्वत: संज्ञान लेकर जांच की थी। इसे उस समय सरकार और डीजीपी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

Andhra HC directs government, NHRC on Seshachalam encounter case

https://www.newindianexpress.com/amp/story/states/andhra-pradesh/2024/Aug/29/andhra-hc-directs-government-nhrc-on-seshachalam-encounter-case

Express News Service

Updated:29th Aug, 2024 at 9:52 AM

VIJAYAWADA: The Andhra Pradesh High Court on Wednesday directed the State government to submit the status report on the hearing of the protest petition filed by the families of the victims of Seshachalam encounter of 'red sanders smugglers' in 2015 against the chargesheet filed by the police in the case.

At the same time, the division bench comprising Chief Justice Dhiraj Singh Thakur and Justice C Ravi, asked the National Human Rights Commission to give a clarity on the inquiry into the issue, as the case is being heard by the High Court.

It directed the NHRC counsel to take a call on whether to continue a parallel inquiry into the issue or not. Later, the case hearing was adjourned to next month.

Following the petition filed by the family members of the encounter victims, the **NHRC** had taken suo motu inquiry of the issue. The same was challenged in the High Court by the government and the DGP at that time.

BIG NEWS NETWORK, Online, 30.8.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

"Group of citizens to submit representation to National Human Rights Council on West Bengal": BJP MP Saumitra Khan

https://www.bignewsnetwork.com/news/274533328/group-of-citizens-to-submit-representation-to-national-human-rights-council-on-west-bengal-bjp-mp-saumitra-khan

ANI 29th August 2024, 14:27 GMT+10

Kolkata (West Bengal) [India], August 29 (ANI): Citing the 'Nabbana Abhijan' rally and its aftermath, BJP MP from Bishnupur, Saumitra Khan said on Thursday that a group of concerned citizens will call upon the chairperson of the National Human Right Commission to submit a representation on the events that took place on August 27 and 28, which he said are a blatant violation of human rights.

In a note, the BJP MP said, "A group of concerned citizens of civil society across the country consisting of Members of Parliament, Former IPS officer, Senior Advocates of the Supreme Court and High Court, and Members of Legislative Assembly amongst others will be calling upon the acting chairperson of the **NHRC (National Human Right Commission)** on August 29 at 2 pm to submit a representation on the unfolding events occurred on August 27 and August 28 in the West Bengal that are blatant violation of human rights."On Wednesday, Union Minister Sukanta Majumdar staged a sit-in protest on the road at Baguiati in Kolkata during the 12-hour 'Bengal Bandh' called by BJP in Bengal.

Majumdar also wrote a letter to Union Home Minister Amit Shah against Chief Minister Mamata Banerjee for advocating violence and said that "shamelessly inciting gathering" by the West Bengal CM is nothing less than a blatant endorsement of revenge politics from the highest office in the state.

BJP had called for a '12 hour Bengal Bandh' on Wednesday after Kolkata police resorted to lathi charges, the use of water cannons and tear gas against the protestors in Nabnna Abhiyaan' Rally.

The rally termed "Nabanna Abhiyan" started from the College Square in the capital of West Bengal, amid heightened security around the West Bengal state secretariat with protestors gathering at the Santragachi area in Howrah.

On August 27, chaos broke out in the streets of Kolkata. Security personnel lobbed tear gas shells, used water cannons and resorted to lathi-charge to disperse protestors on the Howrah Bridge marching towards the West Bengal State Secretariat Nabanna, amidst the growing protests over the RG Kar Medical College and Hospital rape-murder case.

BIG NEWS NETWORK, Online, 30.8.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

The murder and alleged sexual assault of a female trainee doctor on August 9 at RG Kar Medical College and Hospital caused national outrage and many rallies have been held in different states of the country. (ANI)

How The Case Against Kashmiri Activist Khurram Parvez Criminalises Human Rights Reports & Fact-Finding

https://kashmirtimes.com/how-the-case-against-kashmiri-activist-khurram-parvez-criminalises-human-rights-reports-fact-finding/

AdminComment ArticlesIndiaOpinion 14 hours ago 19 min read

"A criminal case registered against Kashmiri activist Khurram Parvez, imprisoned for nearly three years under India's counter-terrorism law, cites two reports produced by his civil society organisation on human rights violations and the impunity enjoyed by security forces and the police in Jammu and Kashmir. In citing them as evidence of tarnishing India's image and promoting secessionism under the garb of human rights, Prime Minister Narendra Modi's government is criminalising crucial human rights research and fact-finding, said lawyers, setting a precedent that could have a chilling effect on other groups doing similar work."

Betwa Sharma

In the terrorism case registered against Kashmiri human rights activist Khurram Parvez, the National Intelligence Agency (NIA) has cited two human rights reports as evidence that his non-profit was promoting secessionism and tarnishing India's image under the garb of human rights work in Jammu and Kashmir (J&K).

Parvez, 47, was the programme coordinator of the Jammu and Kashmir Coalition of Civil Society (JKCCS), a nonprofit coalition of human rights, advocacy, and research groups started by a Kashmiri lawyer, Parvez Imroz, in 2000.

Over two decades, the JKCCS published 18 reports on human rights violations and the impunity enjoyed by security forces and the police in the erstwhile Muslim majority state, now a union territory, ravaged by a Pakistan-backed insurgency since the 1990s.

Lawyers said the NIA appeared to criminalise human rights reports by citing the Structures of Violence Report (published in 2015) and the Torture Report (published in 2019) as evidence in a case registered under India's counterterrorism law, the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), 1967.

This sets a dangerous precedent, they said, that could have a chilling effect on other groups investigating human rights violations and producing critical reports.

Mihir Desai, a senior advocate who practises in the Bombay High Court and the Supreme Court and has collaborated with the JKCCS on human rights reports, said the NIA cited the reports to prevent any critical voices from coming out of Kashmir.

"The present establishment is criminalising any narrative that is different from their own narrative," said Desai. "Anything written about human rights violations is going to be frowned upon. If it is Kashmir, it will be frowned upon even more."

“They are saying there is no reality except what we tell you,” he said.

Criminalising Fact-Finding & Human Rights Work

Before the Supreme Court stayed the amendment to India’s information technology rules in March, a union government fact-checking unit was supposed to identify “fake,” “false,” or “misleading” online content related to the government’s “business” to stop the creation of fake news or misinformation.

The government would rescind the legal immunity of online intermediaries and Internet service providers against the content shared by users if they did not remove or block content identified by the fact-checking unit.

A recent example of criminalising a fact-finding report was a September 2023 Manipur police case under the Indian Penal Code for “promoting enmity between different groups” after a media body published its findings on the media coverage of the conflict in the northeastern state.

Finding the Editors Guild of India report to be “one-sided”, chief minister N. Biren Singh said, “They are anti-State, anti-national and anti-establishment, who came to pour venom…”

Stopping the Manipur police from arresting guild members, a three-judge bench of the Supreme Court questioned whether a report could lead to a criminal case. “It is a report after all,” they said. “Can that be the subject matter of a criminal case?”

Kartik Murukutla, a Delhi-based lawyer who worked with the JKCSS for seven years, said the case against Parvez and the JKCSS’ reports were “significant because it was the first time a charge sheet under terror laws had been filed against a human rights group with the public work of the organisation under attack”.

“The State seeks to use the procedure of the law to shut down human rights work,” said Murukutla. “Human rights documentation—where the State has refused to investigate, and the local judicial remedies have been exhausted—is crucial.”

“Under the garb of terror and a regressive interpretation and application of the terror laws, the State is criminalising what is internationally recognised work, including the use and application of international law by human rights groups operating in conflict zones,” said Murukutla.

The Case Against Parvez

The NIA case in which Parvez was arrested on 22 March 2023 alleged that the JKCCS was not registered as a non-governmental organisation or under the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA), 2010, which allows an organisation to get foreign funding.

The federal agency alleged the JKCCS was getting money and working on behalf of the intelligence agency of Pakistan, commanders of the Hizbul Mujahideen terrorist group

and separatists based in Pakistan Occupied Kashmir and Kashmir to foster unrest, organise stone pelting, strikes and protests, promote secessionism, instigate young men to Pakistan to join the insurgency, give monetary support to the families of active, arrested, and dead militants, and fuel the violence.

The first information report (FIR), registered on 18 October 2020, did not mention Parvez, JKCCS or any other organisation but read like a vague and open indictment of “NGOs, Trusts and Societies”, which the NIA said were “part of a larger criminal conspiracy” that was “prejudicial to the unity, integrity, sovereignty and security of India”.

Parvez was arrested in this case nearly two-and-a-half years after it was registered. He was, however, already jailed since 22 November 2021, when he was arrested in a case registered on 6 November under the UAPA, where he was accused of being part of a “larger conspiracy” of recruiting overground workers for Lashkar-e-Taiba, another terrorist group based in Pakistan.

‘The Next Frontier Of War’

Parvez’s arrest came, as Article 14 reported in November 2021, 10 days after India’s national security adviser Ajit Doval said civil society was ‘the next frontier of war’.

Indeed, “waging war” was one of the eight charges Parvez faced at the time.

“The new frontiers of war, what you call the fourth generation warfare, is the civil society,” said Doval, addressing police probationers at the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Academy in Hyderabad on 13 November 2021.

“Wars have ceased to become an effective instrument for achieving political or military objectives,” said Doval. “They are too expensive or unaffordable, and, at the same time, there is uncertainty about their outcome. But it is the civil society that can be subverted, suborned, divided, and manipulated to hurt the interests of a nation. You are there to see they stand fully protected.”

Doval’s remarks appeared to be translated into policy, as a crackdown against Parvez and others indicated.

Others accused in the 18 October 2020 case are Kashmiri journalist Irfan Mehraj, Ghulam Hassan Ganai (Ghulam Hassan Bana), the alleged commander of the Hizbul Mujahideen and the convenor of the All Party Hurriyat Conference (APHC) of Pakistan Occupied Kashmir, Parvez Imroz, president of the JKCCS, and Natasha Rather, a member of the JKCCS.

Mehraj, 32, was arrested on 20 March 2023, and the NIA has filed a charge sheet or a document formally accusing him of a criminal offence. The NIA has chargesheeted Bana, too, but he is absconding. Imroz and Rather have not been chargesheeted.

Parvez and Mehraj are accused of raising funds for a terrorist act, conspiracy to commit a terrorist act, recruiting a person for a terrorist act, and supporting and raising funds for a terrorist organisation.

“Parvez has been incarcerated in Delhi’s Rohini jail for over 1,000 days.”

While their work would be defended if a trial ensued, Murukutla said it was important that those arrested be released on bail pending trial.

Imroz, a lawyer, said he founded JKCCS to fight fundamentalism and promote democracy, transparency and accountability.

“We started the civil society initiative because we never trusted politicians here. We thought the best way to fight extremism was to strengthen civil society and a culture of reason,” said Imroz. “We were doing things within a legal framework. We have not thwarted any law because we believe it gives us security.”

“The criminalisation of this initiative has resulted in it being completely aborted. As a result, there is a void. We don’t know what is happening,” he said. “Without a vibrant civil society, democracy is only a word.”

First Report In The Chargesheet

The report on the structure of violence, published in 2015, said it sought to analyse the role of the state in Jammu and Kashmir, which had resulted in more than 8,000 disappearances, 70,000 deaths, 6,000 unmarked mass graves and countless cases of torture and sexual violence.

The chargesheet said the report gave away “intricate details of deployment”, details of police and army officers posted in sensitive areas and their alleged crimes, and that it was “false and fabricated” and published to “tarnish the image of India at international level…”

The NIA said that a draft of the report was “shared from time to time with Pakistan-based handlers and terrorists,” and Parvez released it in Pakistan on the invitation of Shah Ghulam Qadir and Altaf Hussain Wani, who are associated with the Kashmir Institute of International Relations, an NGO based in Pakistan.

They said that Qadir was a member of the Pakistan Muslim League and a member of the Pakistan Occupied Kashmir Legislative Assembly, and Wani was a “separatist leader and a key man of the ISI” who was working on the “secessionist agenda” and associated with commanders of the Hizbul Mujahideen. They said that “terrorist commanders” facilitated the release of the report in various forums in Pakistan.

This JKCCS report, which the NIA said was fabricated and gave away details of deployment and officer names, has been available online since it was published in September 2015.

If there was material the authorities wanted to contest or sensitive military information in the report, the government could have communicated with the authors at the time instead of including it in a terrorism case nine years later said lawyers.

Documenting 333 cases of human rights violations—198 case studies on extrajudicial killings (415 persons killed) and 73 cases of enforced disappearances (89 disappeared persons)—the report said the layout of the Indian army structure allowed tracing “the theoretical line that connects individual victim and perpetrator in any neighbourhood in Kashmir all the way to the army and BSF (Border Security Force) in New Delhi”.

“The case studies reiterate the lack of any will to provide justice. Despite overwhelming evidence, the Indian judiciary and executive (supported by the legislature through laws such as AFSPA) do not allow for fair and independent processes of investigation or prosecution,” the report said.

“The list of alleged perpetrators, their ranks, units and areas of operations strongly suggests that the crimes listed within this report occurred across Jammu and Kashmir by various armed forces and the police and at various levels of hierarchy for each of these armed forces and police. The Indian state narrative of human rights violations being mere aberrations is not substantiated on consideration of these cases.”

Lawyers said the Jammu and Kashmir Armed Forces Special Powers Act (AFSPA), 1990, and the Public Safety Act (PSA), 1978, which give sweeping powers to the army and the administration, respectively, are responsible for the existing impunity.

Under the AFSPA, security forces can open fire and even kill a person found in contravention of the law or carrying arms and ammunition in an area the centre determined to be “disturbed”. It allows for arresting people based on “reasonable suspicion” and searching their homes.

“Whether any particular incident in the report is wrong, I don’t know. If you don’t agree with a particular incident, you give your alternate argument. But you can’t criminalise fact-finding as a whole,” said Mihir Desai, who was legal counsel for the International People’s Tribunal on Human Rights and Justice in Kashmir (IPTK), which produced the report on strictures of violence.

“The fact of the matter is that human rights violations at the hands of security forces have been rampant in Kashmir for the past 30 years. That’s a fact. AFSPA and PSA have been used in a very discriminatory manner,” said Desai. “People have been tortured. People have been encountered.”

In a rare instance of justice, a military court in March 2023 convicted an army captain for the “staged encounter” of three people in the northern district of Shopian in Kashmir in July 2020 and recommended life imprisonment.

Nine months later, in response to the captain's appeal, the armed forces tribunal found "defects and perversity" in the case against him, suspended his sentence, and said that acquittal could not be ruled out.

Human Rights In Kashmir

The JKCCS was not alone in documenting extrajudicial killings, enforced disappearances and the failure of the Indian state to respond to human rights violations in Kashmir. Human Rights Watch, Amnesty International, the United Nations, the National Human Rights Commission, and the now defunct State Human Rights Commission have called attention to these violations and urged the government of India and authorities of the erstwhile state to address them.

In 2003, while seeking information from the state on enforced disappearances, the **National Human Rights Commission** said, "…the Government of J&K sent a reply which was singularly silent about the establishment of a system to record allegations of enforced or involuntary disappearances or the nature of that system. It has also not informed the Commission about the number of allegations, the details of the system established to investigate the allegations and the results of those investigations."

India signed the International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance 2006 in 2007 but did not ratify it.

In 2008, the European Parliament, a legislative body of the European Union, passed a resolution calling on "the government of India to urgently ensure independent and impartial investigations into all suspected sites of mass graves in Jammu and Kashmir" and "to investigate all enforced disappearances…"

In 2015, the Association of Parents of Disappeared Persons (APDP) in Srinagar, which estimates that 8,000 to 10,000 Kashmiri civilians have disappeared since 1989, asked the Jammu and Kashmir government at the time to form an independent commission, co-chaired by two retired Supreme Court justices and comprising international experts, to probe "enforced disappearances and unknown, unmarked and mass graves, within a time frame".

This was four years before the Modi government rescinded Jammu and Kashmir's semi-autonomous status in August 2019 and made the country's only Muslim-majority state a union territory, bringing it under the direct control of the central government.

The abrogation in August 2019 was followed by the closure of the state human rights commission, formed in 2007, which was investigating hundreds of cases of human rights violations, including mass graves, enforced disappearances, extra-judicial killings and rape.

The commission, a four-member panel with a recommendatory, supervisory, and advisory role, was a toothless tiger, but it gave people hope.

In 2019, Abdul Rashid Khan, a resident of Kupwara district, told HuffPost India, “My son had disappeared 14 years ago. My case was at its final stage, and suddenly, the commission was shut. I feel shattered today.”

Bad To Worse

Successive governments have failed to address human rights violations and hold the security forces in Kashmir accountable for enforced disappearances, extra-judicial killings and torture.

But the past 10 years since the Bharatiya Janata Party came to power have witnessed a crackdown on the limited freedom the media and civil society groups had to report such cases, prosecuting journalists and activists for grave crimes like being part of a terrorist conspiracy and terrorist funding.

Several similarly crafted cases had spun a narrative where media outlets and civil society groups critical of the government are said to be using foreign funding to promote secessionism and militancy under the garb of human rights and journalism.

Given the abdication of the mainstream media to the government in the past decade, the disappearance of these smaller, more independent outlets has meant there is almost no one left to report on the human rights violations in the conflict-ridden region where the insurgency appears to be worsening and spreading to previously peaceful areas.

In February 2023, Article 14 reported how the NIA’s terrorism case against journalist Fahad Shah, who ran one of the last independent news websites in Kashmir, was based on assumptions and an exercise in retribution.

The NIA alleged that Shah was working with Pakistan handlers and conspirators to produce journalism that led to an “increase in terrorism” and “motivated” young men to join the militancy.

While granting bail to Shah in November 2023, the Jammu and Kashmir High Court quashed the charges of terror conspiracy and waging war against the nation while retaining the ones on unlawful activities and receiving foreign funding illegally.

How It Started

As the insurgency became more and more entrenched in the nineties, Kashmir, home to eight million people, became one of the most militarised zones in the world.

As the number of locals being picked up by the army and police rose, Parvez Imroz, a lawyer, co-founded the APDP (Association of Parents of Disappeared Persons) with Parveen Ahangar, a Kashmiri woman whose son had disappeared after security forces picked him on 18 August 1990.

“I want every single mother in Kashmir and other places whose sons have been forcibly disappeared to get answers to the questions that haunt them: where is my child? Where

did you take them? Bring the dead body if you killed them – but for God's sake, bring them back," she wrote in 2019.

Khurram Parvez, who hold a Masters degree in mass communication and journalism from Kashmir University, joined the APDP in 1997. He received the 2006 Reebok Human Rights Award and the 2023 Martin Ennals Award.

In 2000, Imroz, Khurram and other human rights activists started the JKCCS, a coalition of human rights, research and advocacy groups.

The JKCCS started filing cases related to disappearances and extended them to other human rights violations. They also published reports.

In 2004, JKCCS monitored the Assembly and Parliament elections.

While gathering information in Kupwara district, the jeep carrying Khurram hit a landmine. He survived, but his leg had to be amputated. The driver, Ghulam Nabi Sheikh, was injured. Aasia Jeelani, a journalist, died.

The JKCCS was instrumental in forming the Asian Federation Against Disappearances (AFAD) based in the Philippines, which brought together civil society groups from different countries that started lobbying the United Nations to take a stronger stand against the problem.

In 2014, Khurram became the chair of the AFAD, which the NIA has identified as one of the alleged conduits of funding foreign funds into India without an FCRA license.

Imroz said that the JKCSS wanted to be part of civil society on the mainland and the global civil society.

"Long ago, civil society was said to be the second superpower," said Imroz.

"The young generation in Kashmir was very much for this initiative. This gave the people a vent," he said. "But after the cases and the arrests, the process has been arrested. There is a big vacuum."

In 2016, there was violent unrest in Kashmir after the security forces killed a young Hizbul Mujahideen commander named Burhan Wani.

Khurram was accused in four cases of rioting, unlawful assembly, hurting a public servant, and endangering human life and the personal safety of others.

A preventive detention order was slapped on him.

Second Report In The Chargesheet

The second report that the chargesheet cited, Torture: Indian State's Instrument of Control in Indian Administered Jammu and Kashmir, published in 2019, documented 432 cases.

“Due to legal, political and moral impunity extended to armed forces, not a single prosecution has taken place in any case of human rights violations in Jammu and Kashmir,” the JKCCS said at the time.

“The widespread use of torture continues unabatedly in Jammu and Kashmir,” it said, citing the 2019 example of Rizwan Pandith, a 29-year-old school principal, who died in police custody in March 2019.

The chargesheet said “a number of individuals” had given statements that “clearly establish that the said report was just another tool in spreading concocted stories about human rights violations in Kashmir”.

Imroz said JKCCS reported what the victims stated.

Torture in Kashmir has been widely documented.

In a 2019 report, the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) said, “No security forces personnel accused of torture or other forms of degrading and inhuman treatment have been prosecuted in a civilian court since these allegations started emerging in the early 1990s.”

The UN report relied heavily on the work done by the JKCCS.

Rejecting the report, the Indian government said it was “fallacious, tendentious and motivated”.

India signed the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in October 1997 but has not ratified it.

In May 2020, four UN special rapporteurs listed 14 Kashmiri Muslims and said, “…we express grave concern at the alleged excessive use of force, torture and other forms of ill-treatment reportedly committed during the arrest and detention” and urged the government “to conduct a prompt and impartial investigation into the allegations of arbitrary killings, torture and ill-treatment and to prosecute suspected perpetrators…”

In March 2021, the five UN rapporteurs wrote to the government about an “act of reprisal” against a politician and grassroots activist, Waheed Para, after he spoke with members of the UN Security Council about the treatment of Muslim minorities in India.

Para “was held in a dark underground cell at subzero temperature, was deprived of sleep, kicked, slapped, beaten with rods, stripped naked and hung upside down”, the rapporteurs said.

Para, who contested the 2024 general election from Kashmir, was arrested twice between November 2020 and January 2021; the first time was under India’s counterterrorism law.

While granting him bail in the terror case, a special court of the NIA said the offences under the UAPA were not prima facie made out. While granting him bail in the second

case alleging links to militant groups and financing terrorist activities, the Jammu and Kashmir High Court said the evidence against him was “too sketchy”.

Calling for Khurram’s release in March 2023, the then UN special rapporteur on human rights defenders, Mary Lawlor, said, “The Jammu and Kashmir Coalition of Civil Society carries out essential work monitoring human rights. Their research and analysis of human rights violations are of huge value, including to international organisations seeking to ensure accountability and non-repetition of abuses.”

Mumbai: NCDRC Criticises ESIC Officials For Negligence, Orders ₹50 Lakh Compensation Over Woman's Death

https://www.freepressjournal.in/mumbai/mumbai-ncdrc-criticises-esic-officials-for-negligence-orders-50-lakh-compensation-over-womans-death

The NCDRC not only awarded a hefty compensation to the complainant, but also directed the guilty authorities to form a trust in memory of the deceased and deposit Rs 35 lakh as a corpus funds in it, to be used for underprivileged girls.

Pranali LotlikarUpdated: Friday, August 30, 2024, 01:04 AM IST

The National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) has issued a scathing verdict against the senior state medical commissioners of the Employees' State Insurance Corporation (ESIC) in Hyderabad, Mumbai and Delhi, reprimanding them for their failure to provide timely medical assistance funds to an employee, resulting in the death of her 25-year-old daughter.

The NCDRC not only awarded a hefty compensation to the complainant, but also directed the guilty authorities to form a trust in memory of the deceased and deposit Rs 35 lakh as a corpus funds in it, to be used for underprivileged girls.

The case involved Manda Kumari, a resident of Hyderabad and a member of the ESIC, who sought medical support for her daughter, Shanti Ayani. Shanti was diagnosed with blood cancer in 2011 after initially experiencing frequent colds and fevers. Medical assessments recommended a bone marrow transplantation, for which the Tata Memorial Centre (TMC) estimated a treatment cost of Rs 50 lakh.

Despite a letter of credit issued to TMC in November 2012, the hospital requested a deposit before commencing treatment. However, ESIC delayed the release of funds despite repeated reminders. The situation became dire and Kumari approached the prime minister and the **National Human Rights Commission** for intervention. Additionally, a writ petition was filed with the Andhra Pradesh High Court, which issued an interim order directing the immediate release of funds. This order, too, was ignored by ESIC.

Due to the lack of funds, Kumari was forced to admit her daughter to a different hospital for chemotherapy in October 2013. Within a month, Shanti succumbed to her illness.

The state commission, when it heard the case, found the authorities guilty of negligence and awarded a compensation of Rs5 lakh to Kumari. Unsatisfied, Kumari appealed to the NCDRC for a higher compensation.

In its defence, ESIC argued that the delay in disbursing the funds was due to the time taken to verify the authenticity of the claim, despite having issued a letter of credit to TMC. ESIC contended that by the time the funds were approved for release, the patient had already passed away.

However, the NCDRC found this explanation inadequate and held ESIC accountable for the “inordinate delay” in processing the claim, which directly contributed to Shanti’s untimely death. The commission criticised the initial compensation of Rs 5 lakh as “too meagre”.

The NCDRC ruled: “After thoughtful consideration of the entire facts and circumstances of the case, and the inordinate delay in sanctioning or disbursing the amount to which the complainant was entitled, which ultimately led to the unfortunate and untimely death of her daughter, we are of the considered view that the compensation of Rs5 lakh awarded by the state commission is too meagre. The complainant definitely deserves a much higher compensation.”

The commission awarded a total compensation of Rs 50.75 lakh, the amount initially sanctioned for treatment, payable with 6% interest from 2013. The NCDRC directed that Rs15 lakh be immediately released to Kumari’s account, while the remaining amount is to be deposited in a public sector bank.

The NCDRC ordered the authorities to immediately form a trust in memory of Shanti Ayani, using the corpus fund to support the education and health of underprivileged girls in the area.

ODISHA BHASKAR, Online, 30.8.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC Seeks Report on Rise in Snakebite Deaths in Odisha

https://odishabhaskar.in/odisha/nhrc-seeks-report-on-rise-in-snakebite-deaths-in-odisha-91517/

By Sib Kumar Das On Aug 29, 2024 at 5:01 PM

Bhubaneswar: The **National Human Rights Commission (NHRC)** has issued notice to Odisha Chief Secretary seeking detailed report regarding the steps being taken by the government to reduce snakebite deaths in the State, reported The Statesman.

The NHRC sent this notice following a petition filed by human rights lawyer Radhakanta Tripathy. In the petition, the activist had sought NHRC's intervention on the lack of government measures to check the rising cases of snakebite deaths.

The petitioner noted a series of incidents of snakebite reported in hospitals, police stations, schools, Anganwadi centres, residential homes in Odisha as well as State Government's failure to ensure safety and security at public places including the government offices.

In Last eight years, more than 7,000 persons have died due to snakebites in Odisha, noted the petition.

The NHRC sought replies from the concerned authorities regarding the matter within eight weeks. The NHRC also sought replies on the awareness programmes and availability of the requisite quantity of anti-venom serum in the Public Health Centres and Community Health Centres, whether monetary relief is being provided in a time bound manner to the victims/ next of kin of snakebite victims.

Odisha was the first State in the country to declare snakebite death as a State-specific disaster. From April 1, 2015, snakebites have been declared as a 'State Specific Disaster' by Odisha government. As per reports, around 900 people die of snakebites every year in Odisha.

NHRC seeks report on spurt in snakebite fatalities in Odisha

https://www.thestatesman.com/india/nhrc-seeks-report-on-spurt-in-snakebite-fatalities-in-odisha-1503337171.html

A petition filed earlier by human rights lawyer Radhakanta Tripathy had sought NHRC's intervention on the lack of measures on part of the government to combat the rising cases of snakebite deaths.

Statesman News Service | BHUBANESWAR | August 29, 2024 4:17 pm

The National Human Rights Commission (**NHRC**) has issued notice to Odisha Chief Secretary seeking detailed report regarding the steps being taken by the government to reduce snakebite fatalities in the State.

A petition filed earlier by human rights lawyer Radhakanta Tripathy had sought NHRC's intervention on the lack of measures on part of the government to combat the rising cases of snakebite deaths.

The petitioner had highlighted a series of incidents of snakebite reported in hospitals, police stations, schools, Anganwadi centres, residential homes in Odisha and failure of the State Government to ensure safety and security at public places including the government offices.

Due to the Government's lack of attention to it, more than 7,000 precious human lives were lost in the last eight years in the State, the petition noted.

Seeking replies from the authorities concerned within eight weeks, the top rights panel pointed out whether the authorities obtained opinions from the experts to minimise the incidents of the snakebites. The panel also sought replies on the awareness programmes and availability of the requisite quantity of anti-venom serum in the Public Health Centres and Community Health Centres.

The NHRC also sought to know whether monetary relief is being provided in a time bound manner to the victims/ next of kin of snakebite victims.

The snake bites, which has been declared as a 'State Specific Disaster' by Odisha government from 1 April, 2015, claim close to 900 human lives every year, according to officials of Special relief commissioner's office.

It's pertinent to note here that Odisha was the first State in the country to declare snakebite death as a State-specific disaster.

Saumitra Khan का दावा, "ममता बनर्जी सत्ता में वापस आईं तो 'सिलीगुड़ी कॉरिडोर' को रोक सकती हैं"

https://jantaserishta.com/delhi-ncr/saumitra-khan-claims-if-mamata-banerjee-comes-back-to-power-she-can-stop-the-siliguri-corridor-3492566

Gulabi Jagat29 Aug 2024 1:49 PM

New Delhi नई दिल्ली : भाजपा सांसद और पश्चिम बंगाल भाजपा उपाध्यक्ष सौमित्र खान ने गुरुवार को एक बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया कि ममता बनर्जी अगर 2026 में फिर से सत्ता में आती हैं तो वह पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाले 'सिलीगुड़ी के चिकन नेक कॉरिडोर' को बंद कर सकती हैं। खान ने दावा किया कि वह अपनी राजनीति के लिए आतंकवादियों और अपराधियों को बढ़ावा दे सकती हैं। उन्होंने शीर्ष अदालतों और भारत सरकार से इस संबंध में संज्ञान लेने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा उपाध्यक्ष सौमित्र खान ने कहा, "मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूं और मुझे डर है कि अगर भारत सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो ममता बनर्जी 2026 तक सिलीगुड़ी हिस्से में भारत के (चिकेंस) नेक को बंद करके पूर्वोत्तर

भारत का रास्ता बंद कर देंगी। वह राजनीति के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वह अपनी राजनीति के लिए आतंकवादियों और अपराधियों को बढ़ावा देंगी। अदालतों और भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा भारत खतरे में पड़ जाएगा।" पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी के खिलाफ हिमंत बिस्वा सरमा के ट्वीट पर खान ने कहा, "असम एक विकासशील राज्य है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के सत्ता में आने के बाद, असम के लोगों को असम में, उनके घरों में काम मिल रहा है।

रोजगार बढ़ रहा है और उद्योग स्थापित हो रहे हैं। दूसरी ओर, ममता बनर्जी बंगाल को बर्बाद कर रही हैं। मुझे भी लगता है कि वह विदेशी शक्तियों से जुड़ी हुई हैं।" इससे पहले बुधवार को, भाजपा के 12 घंटे लंबे 'बंगाल बंद' के आह्वान पर कोलकाता में एक सार्वजनिक समारोह में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता की महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर बंगाल में आग लगाने के लिए अपनी पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं और चेतावनी दी कि यदि आप बंगाल को जलाते हैं, तो

असम, पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली सहित अन्य राज्य भी जलेंगे और आपकी कुर्सी गिर जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा, "कुछ लोगों को लगता है कि यह बांग्लादेश है। मुझे बांग्लादेश से प्यार है; वे हमारी तरह बोलते हैं और हमारी संस्कृति साझा करते हैं। लेकिन याद रखें, बांग्लादेश एक अलग देश है, और भारत एक अलग देश है। मोदी बाबू अपनी पार्टी का इस्तेमाल यहां आग लगाने के लिए कर रहे हैं। अगर आप बंगाल जलाएंगे, तो असम, पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे! हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे।" एक्स पर एक पोस्ट में, असम के मुख्यमंत्री ने सीएम ममता पर भी निशाना साधा और कहा, "दीदी, असम को धमकाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हमें लाल आंखें मत दिखाइए। अपनी विफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। विभाजनकारी भाषा बोलना आपको शोभा नहीं देता।" एनएचआरसी के एक प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर बोलते हुए, जिसमें भाजपा नेता शामिल थे, खान ने कहा, "आरजी कर मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एनएचआरसी

(राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगा क्योंकि आरजी कर अस्पताल की घटना में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हम प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ (एनएचआरसी) जा रहे हैं।" इससे पहले दिन में 'नब्बाना अभिजन' रैली और उसके बाद की घटनाओं का हवाला देते हुए सौमित्र खान ने कहा कि चिंतित नागरिकों का एक समूह **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** के अध्यक्ष से 27 और 28 अगस्त को हुई घटनाओं पर एक ज्ञापन सौंपने का आह्वान करेगा, जिसे उन्होंने मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन बताया। (एएनआई)

What does Himachal Pradesh's Bill raising women's minimum marriage age entail?

https://www.thehindu.com/news/national/himachal-pradesh-bill-womens-minimum-marriage-age-entail/article68580118.ece

What are the key provisions of the Bill? Why is the assent of the President required? What are the concerns?

Updated - August 30, 2024 02:59 am IST

Published - August 29, 2024 09:02 pm IST

The Himachal Pradesh Assembly on Tuesday (August 27, 2024) passed a Bill raising the minimum marriageable age for women from 18 to 21 years. The Prohibition of Child Marriage (Himachal Pradesh Amendment) Bill, 2024, was passed by voice vote on the first day of the two-week monsoon session. It seeks to amend the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (2006 Act) to advance gender equality and encourage higher education among women.

The Bill was initially introduced in the Vidhan Sabha during the Budget session in February but could not be passed then. Earlier, in June, a central bill that aimed to bring uniformity in the minimum age of marriage for men and women lapsed with the dissolution of the 17th Lok Sabha. The Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2021 was introduced in the Lok Sabha in December 2021 and was subsequently referred to a parliamentary standing committee for review. However, despite receiving multiple extensions, the 31-member committee failed to table its report.

Why was the Bill passed?

Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu told The Hindu that the passage of the Bill clearly demonstrates the Congress government's commitment to advancing the welfare of women. "We are the first State in the country to enact the legislation to increase the marriage age of girls to 21. The Congress has always been at the forefront to work towards the betterment of women," Mr. Sukhu said.

Tabling the Bill in the House, Health, Social Justice, and Empowerment Minister Dhani Ram Shandil highlighted that early marriage obstructs girls' education and limits their potential for progress in life. He noted that the proposed amendments to the 2006 Act aim to reduce instances of early pregnancies and motherhood, which adversely affect women's health.

"In today's world women are progressing in every field. The early marriages, however, act as a hindrance not only in the progress of their career but also in their physical

development. In order to provide for gender equality and opportunities to obtain higher education, it has become necessary to increase the minimum age of marriage for girls. Thus, it is proposed to amend the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 and other related Acts in their application to the State of Himachal Pradesh and increase the minimum age for marriage for girls to 21 years," the Bill stipulates.

What are the key provisions?

Currently, Section Section 2(a) of the 2006 Act defines a "child" as someone "who, if male, has not completed twenty-one years of age, and if female, has not completed eighteen years of age." The Bill removes this gender-based distinction, redefining a "child" as "a male or female who has not completed twenty-one years of age."

The Bill also extends the time period for filing a petition to annul a marriage. Under Section 3 of the 2006 Act, an individual who was a minor at the time of marriage can file for annulment within two years of attaining majority —before turning 20 for women and 23 for men. The Bill extends this period to five years, allowing both women and men to file petitions before they turn 23, in accordance with the new minimum marriageable age of 21 years.

A new provision, Section 18A, has also been introduced to ensure that the Bill's provisions take precedence over all other existing laws. This means that the new minimum marriageable age for women will apply uniformly across Himachal Pradesh, regardless of any conflicting laws or religious and cultural practices.

Why will the President's assent be required?

The Concurrent List of the Seventh Schedule of the Constitution outlines subjects on which both the central and state governments can legislate. Entry 5 of this list deals with the subject of marriage and divorce enabling both the Centre and states to enact laws to regulate child marriages.

After a Bill is passed by a State Legislative Assembly, it is presented to the Governor for assent. Under Article 200 of the Constitution, the Governor can exercise four options — to grant assent, withhold assent, return the Bill to the Assembly for reconsideration, or reserve it for the President's consideration. A Bill can be reserved for the President's consideration only if the Governor believes that it could undermine the authority of the High Court.

In this case, Governor Shiv Pratap Shukla's assent would typically suffice to enact the Bill into law. However, since the Bill introduces a different minimum marriageable age

for women, its provisions will be deemed inconsistent with the 2006 Act —a law enacted by Parliament. This potential conflict brings Article 254 of the Constitution into play. According to clause (1) of this provision, if a State legislature enacts a law on a subject covered by the Concurrent List that is "repugnant" to the provisions of an existing central law, then that repugnant or inconsistent portion of the state law will be considered "void".

However, if the State legislation is reserved for the President's consideration and receives his or her assent in accordance with clause (2) of Article 254, then its validity can be upheld. With the President's assent, the state law will take precedence within the State and override the provisions of the central law in their applicability to the State only. Thus, for the Himachal Pradesh Bill to come into force, the Governor must reserve it for President Droupadi Murmu's consideration, who must then decide to give her assent to the Bill.

What do experts have to say?

Child and women's rights activists have long opposed raising the minimum age for marriage. They argue that the existing provisions of the 2006 Act are frequently exploited by disapproving parents to penalise daughters who pursue inter-caste or inter-religious marriages against familial wishes. In a patriarchal society, increasing the minimum marriage age may further entrench parental control over young adults.

Author and activist Madhu Mera previously told The Hindu that raising the minimum marriage age for women to 21 years could upend young lives in a web of criminal prosecutions. "In our research at Partners for Law in Development, we looked at 10 years of use of the child marriage law. Overwhelmingly, the law was used by parents against eloping daughters. It has become a tool for parental control and for punishment of boys or men whom girls choose as their husbands. An increase in age to 21 years would mean further persecution of girls right up till 21 years," she said.

Such a legislative reform could also leave a vast majority of Indian women who marry before the age of 21 years without the legal protections that the institution of marriage otherwise provides. It is also likely to endanger the life and liberty of the marginalised communities exposing them to further brutal policing. The 2008 Law Commission Report recommended setting a uniform age of marriage for both men and women at 18 years. The **National Human Rights Commission** in 2018 too proposed a similar reform.

भयावह रूप से क्यों गायब हो रही हैं भारत से महिलाएं और लड़कियां?

https://janchowk.com/zaruri-khabar/why-are-women-and-girls-disappearing-from-india-at-such-an-alarming-rate/?noamp=available

August 29, 2024 स्वदेश सिन्हा

आज देश में महिलाओं और लड़कियों के प्रति अपराधों में भयानक रूप से वृद्धि हो रही है, विशेष रूप से बलात्कार के मामले में। देश का कोई राज्य इससे अछूता नहीं है। इसके प्रति कड़े कानून भी बनाए गए, बावज़ूद इसके यह सिलसिला थमने को नहीं आ रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने राजनीतिक हितों के अनुरूप ही महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे उठाते हैं।

पिछले दिनों कोलकाता में एक महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में इन चीज़ों को भलीभांति देखा जा सकता है। महिलाओं के साथ केवल बलात्कार के मामले ही नहीं है, बल्कि देश भर में महिलाओं और लड़कियों के ग़ायब होने तथा उनके अपहरण के मामले भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उससे सम्बन्धित आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं।

देश में 2019 से 2021 के बीच लापता हुई लड़कियों और महिलाओं में सबसे अधिक लगभग दो लाख लड़कियां मध्य प्रदेश से और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2019 से 2021 के बीच देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु की 10,61,648 महिलाएं और उससे कम आयु की 2,51,430 लड़कियां लापता हुईं।

फेमिनिज़्म इन इंडिया यूएनएफपीए की रिपोर्ट बताती है कि यदि भारत की जनसंख्या वर्तमान दर से, जो लगभग एक प्रतिशत प्रतिवर्ष है, इसी तरह बढ़ती रही तो अगले 75 वर्षों में यह वर्तमान से दोगुनी हो जाएगी, लेकिन भारत महिला जनसंख्या के मामले में आज भी पिछड़ा हुआ है और यहां महिलाओं और लड़कियों की संख्या अनुमान से करोड़ों कम है।

हमारे देश में महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा का एक क्रूर रूप है महिलाओं का लापता हो जाना। अफसोस की बात है ये महिलाओं और किशोरियों की आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति, सामाजिक और यहां तक कि राजनीतिक स्थिति से भी जुड़ी है।

देश में लापता महिलाओं और लड़कियों की व्यापक वास्तविकता बेहद चिंताजनक और निराशाजनक है। हाल ही में विधानसभा में कांग्रेस विधायक और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद आधिकारिक आंकड़ों में पता चला है कि पिछले तीन सालों में मध्य प्रदेश में 31,000 से ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं। कुल लापता लोगों में से 28,857 महिलाएं और 2,944 लड़कियां साल 2021 से 2024 के बीच लापता हुईं।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट मुताबिक मध्य प्रदेश में हर दिन औसतन 28 महिलाएं और तीन बच्चे लापता होते हैं, इसके बावजूद आधिकारिक तौर पर सिर्फ 724 मामले ही दर्ज़ किए गए। पिछले 34 महीनों में उज्जैन में कुल 676 महिलाएं लापता हुईं, लेकिन एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ।

रिपोर्ट बताती है कि राज्य के सागर जिले में सबसे ज्यादा 245 लड़कियां लापता हुईं। वहीं इंदौर में 2,384 मामले दर्ज़ किए गए, जो किसी भी जिले में सबसे ज्यादा है, लेकिन इंदौर में केवल 15 मामले दर्ज़ किए गए, जबकि इस में इस क्षेत्र में एक महीने में लापता मामलों की संख्या 479 है।

साल 2023 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2021 के बीच लापता लड़कियों और महिलाओं की संख्या 1.31 मिलियन से भी ज़्यादा थी। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का लापता होना देश में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट से पता चलता है कि इसी समयावधि के दौरान 18 वर्ष से अधिक आयु की दस लाख से अधिक महिलाएं और 18 वर्ष से कम आयु की 25 लाख लड़कियां लापता हुई हैं।

डेक्कन हेराल्ड की एक खबर मुताबिक 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर शुरू किए गए एनसीआरबी द्वारा किए गए पहले के विश्लेषण का उद्देश्य बाल और महिला तस्करी के लिए अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना था। इस विश्लेषण के अनुसार इन लापता मामलों के कारण जटिल और बहुआयामी हैं, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और गलतफहमी से लेकर घरेलू हिंसा और आपराधिक उत्पीड़न तक शामिल हैं।

साल 2018 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 63 मिलियन लापता महिलाएं और 21 मिलियन अवांछित लड़कियां हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि लापता महिलाओं के लिए सेक्स-सिलेक्टिव अबॉर्शन और पोषण और स्वास्थ्य देखभाल में प्रसवोत्तर उपेक्षा को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये लापता महिलाएं लड़कों के लिए एक मजबूत सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्राथमिकता को दर्शाती हैं।

भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, अर्थशास्त्री अमर्त्य कुमार सेन ने गणना की कि किस प्रकार लिंग अनुपात और लापता महिलाओं की संख्या में परिवर्तित हो जाता है। सेन ने 1992 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में 'लापता महिलाओं' की अवधारणा प्रस्तुत की थी। उन्होंने अनुमान लगाया था कि 100 मिलियन महिलाएं लापता हैं, जिनमें से 80 फीसद भारत और चीन से हैं।

देश में 2019 से 2021 के बीच लापता हुई लड़कियों और महिलाओं में सबसे अधिक लगभग दो लाख लड़कियां मध्य प्रदेश से और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2019 से 2021 के बीच देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु की 10,61,648 महिलाएं और उससे कम आयु की 2,51,430 लड़कियां लापता हुईं।

इस खबर मुताबिक मध्य प्रदेश में साल 2019 से 2021 के बीच 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां लापता हुईं। इसी समय अवधि में पश्चिम बंगाल से कुल 1,56,905 महिलाएं और 36,606 लड़कियां लापता हुईं।

महाराष्ट्र में भी इस समय में 1,78,400 महिलाएं और 13,033 लड़कियां लापता हुईं। इसी तरह इसी समय के बीच ओडिशा में 70,222 महिलाएं और 16,649 लड़कियां लापता हुईं, जबकि छत्तीसगढ़ से 49,116 महिलाएं और 10,817 लड़कियां लापता हुईं। वहीं दिल्ली में इस समय सीमा के बीच 61,0 54 महिलाएं और 22,919 लड़कियां लापता हुईं, जबकि जम्मू कश्मीर से 8,617 महिलाएं और 1,148 लड़कियां लापता हुईं।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) द्वारा जारी 2020 की वैश्विक आबादी की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 सालों में लापता हुईं महिलाओं की संख्या दुगुनी हो गई है। यह संख्या साल 1970 में 6.10 करोड़ थी जो 2020 में बढ़कर 14.26 करोड़ हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में साल 2020 तक 4.58 करोड़ और चीन में 7.23 करोड़ और 23 लाख महिलाएं लापता हुई हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2016, 2017 और 2018 की अवधि में किए गए 'भारत में लापता महिलाएं और बच्चे' अध्ययन में पाया कि देश में 5,86,024 महिलाएं लापता हैं। इसका मतलब है कि भारत में हर दिन 550 से ज़्यादा महिलाएं लापता हो रही हैं।

दुनिया के हर कोने में होने वाला यह अपराध सभी उम्र और पृष्ठभूमि के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को प्रभावित कर सकता है। मानव तस्करी एक गंभीर सामाजिक समस्या है, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए, जो इस समस्या का सामना पुरुषों से अधिक करती हैं। यह उनकी गरिमा और मानवाधिकारों का हनन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार महिलाओं और बच्चों की मानव तस्करी मानवाधिकारों के हनन के सबसे जघन्य प्रकारों में से एक है।

चूंकि यह एक जटिल समस्या है, इसलिए इस पर शिक्षाविदों, कानूनी पेशे और नागरिक समाज ने बहुत कम ध्यान दिया है। इसे अक्सर सेक्स ट्रैफिकिंग से जोड़ा जाता है, जबकि यह मानव तस्करी की कहानियों का सिर्फ एक पहलू है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट 'महिलाओं और बच्चों की तस्करी: चुनौतियां और समाधान' के अनुसार श्रम और यौन तस्करी के लिए, भारत एक स्रोत, गंतव्य और ट्रांजिट देश है। भारत में 90 फीसद तस्करी देश के भीतर होती है, जबकि 10 फीसद राष्ट्रीय सीमाओं के पार होती है।

आंकड़ों के अनुसार भारत में मानव तस्करी किए गए 95 प्रतिशत लोगों को जबरन सेक्स ट्रैफिकिंग में डाल दिया जाता है। 2011 में मानव तस्करी के खतरे के संदर्भ में तस्करी सूचकांक में 196 देशों में से इसे सातवें स्थान पर रखा गया था। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसे संगठनों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए मजबूत, विश्वसनीय और अलग-अलग डेटा प्रणालियों को संभावित तरीकों के रूप में माना है।

2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार, वे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और शासन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नैदानिक कार्य, रोकथाम और प्रतिक्रिया प्रयासों और नीतियों को सूचित करते हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तस्करी की शिकार अधिकांश उत्तरदाता आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से थे। सरकार महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा की बात करती आ रही है। लेकिन लापता होती महिलाओं और लड़कियों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। वहीं ये भी सच है कि ये सिर्फ दर्ज हुए केस हैं, क्योंकि बहुत से लोग लापता के मामले लोक लाज के डर से दर्ज नहीं कराते हैं।

असल में महिलाओं और लड़कियों का गायब होना और मानव तस्करी एक दूसरे से जुड़े हैं और ये बहुआयामी समस्या है, जिसमें गरीबी एक महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए, राज्यों को सभी कमज़ोर परिवारों, विशेष रूप से प्रवासियों और जोखिम में पड़े महिलाओं और किशोरियों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ना चाहिए, ताकि नौकरी या अन्य झांसे के चक्कर में वे मानव तस्करी में न पड़े।

महिलाओं और किशोरियों का गायब होना एक गंभीर समस्या है, जो सामाजिक मानदंडों से जुड़ी है, इसलिए इसे सिर्फ़ कानूनी उपायों, सरकारी कार्यक्रमों या पहलों के ज़रिए संबोधित नहीं किया जा सकता। हमें रोजगार, आजीविका की संभावनाओं की कमी, लैंगिक भेदभाव जैसे गंभीर चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इसकी रोकथाम के लिए सोचना होगा।

दुर्भाग्यवश महिलाओं के साथ हर तरह के अपराध; जिसमें बलात्कार, देहव्यापार और उनका अपहरण जैसे मुद्दे एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। सभी राजनीतिक दल इन मुद्दों को अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए ज़रूर उठाते हैं, लेकिन इसे कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनाते। वास्तव में इसके पीछे वह पुरुष-सत्तात्मक मानसिकता ज़िम्मेदार है, जो महिलाओं और लड़कियों को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है।

(स्वदेश कुमार सिन्हा स्वतंत्र पत्रकार हैं।)